हथकरघा क्षेत्र के लिए सूत की कम आपूर्ति

3560. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में, हथकरघा उद्योग की आवश्यकतानुसार सूत उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो देश में हथकरघा उद्योग के लिए सूत की वार्षिक आवश्यकता कितनी होती है ;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कार्य कर रही कताई मिलों को सूत का उत्पादन करने का उत्तरदायित्व सौंपा है ;

(घ) यदि हां तो इन मिलों के लिए क्या वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उनका सूत का औसतन उत्पादन कितना है; और

(ङ) क्या सूत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए देश में सरकार द्वारा एक नई व्यवस्था कायम करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ख) देश में सूत की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सूत का उत्पादन मांग पर निर्भर करता है जो वर्षवार मौसम के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है तथापि हथकरघा उद्योग के लिए सूती और गैर सूती धागे की वार्षिक आवश्यकता लगभग 400 मिलियन किलोग्राम अनुमानित की गई है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र के लिए सूत एन० टी० सी० की मिलों, सहकारी क्षेत्र की मिलों और प्राइवेट क्षेत्र की मिलों द्वारा तैयार किया जाता है।

(घ) एन० टी० सी० की मिलों द्वारा अप्रैल–जून, 1992 की तिमाही के लिए हैंक यार्न की डिलीवरी 1.07 मिलियन किलोग्राम सूत थी।

(ङ) जी, नहीं।

रेशम का उत्पादन

3561. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रेशम का उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता है ;

(ख) क्या सरकार इस क्षमता का यथा सम्भव उपयोग करके रेशम के अधिकतम उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में, देश में रेशम के उत्पादन से वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि चीन से रेशम आयात करने के लिए कई रियायतें दी गई है; और

(ङ) क्या इस आयात के कारण रेशम के घरेलू उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी हां। देश में कच्चे रेशम का उत्पादन वर्ष 1985–86 में 7807 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 1991–92 में 11863 मीट्रिक टन हो गया। देश में रेशम उत्पादन की संभावना का उपयोग करने के उद्देश्य से 17 राज्यों में

विश्व बैंक/स्विस विकास निगम सहायतित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इसके अलावा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने देश में रेशम के अनुसंधान और विकास तथा आधार भूत सहायता प्रदान करने के लिये एकको का देशव्यापी नेटवर्क स्थापित किया है ।

(घ) और (ङ) भारतीय आयात सूची में रेशम एक प्रतिबन्धित मद है और लाइसेंस के बिना इसका आयात नहीं किया जा सकता है । सामान्यत: ऐसे लाइसेंस जारी नहीं किये जाते हैं । तथापि अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत निर्यातक अपनी कच्ची सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चीन या अन्य किसी देश जिसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं, से कच्चे रेशम का आयात कर सकते हैं । ऐसे आयात को निर्यात दायित्व से जोड़ा जाता है ।

Supply of Cloth by N. T. C. for Defence Services

3562. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) what is the value of Cloth/Linen supplied by National Textile Corporation for use by Defence Forces;

(b) whether Government have received complaint against the price and quality and of material; and

(c) if so, what steps are being taken to redress the same ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) Figures indicating the value of cloth supplied by National Textile Corporation to the Defence Forces during the last three years are as follows :

Year	Value (Rs. in Crores)
1989-90	33.97
1990-91	13.69
1991-92	10.50
1992-93 (upto Jan. '93)	9.10

(b) and (c) Government have not received any specific complaint in regard to price or quality of the material supplied by National Textile Corporation to Defence.

Dismissal of Petition against reservation made to Handlooms

3563. SHRI PRAGADA KOTAIAH : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the petitions filed against 'Reservation' made to handlooms were dismissed on Friday the 5th February, 1993 by the Supreme Court of India;

(b) what are the steps proposed by Government to enforce strictly the reservations made to handlooms; and

(c) whether it is a fact that a representation dated the 13th February, 1993 has been received by Government from a Member of Parliament, suggesting the way in which the reservations to handlooms are to be enforced to help handloom weavers ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) Yes, Sir.

(b) Concerned States and other implementing agencies have been directed to undertake effective enforcement of the Handloom Reservation Orders.

(c) Yes, Sir.